



UPSMA
UP SUGAR MILLS ASSOCIATION

वार्ता The Dialogue

April to June, 2026

Quarterly Newsletter of UPSMA

VOL: IV, ISSUE: 317

NEWSMAKERS

चीनी उद्योग को बदलनी होगी रणनीति, बाय-प्रोडक्ट्स पर बढ़ाना होगा फोकस

गन्ना एवं चीनी आयुक्त मिनिस्त्री एस. ने कहा कि बदलते पर्यावरणीय और औद्योगिक माहौल को देखते हुए चीनी मिलों को अब केवल चीनी उत्पादन तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मिलों को बाय-प्रोडक्ट्स और मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्माण की दिशा में तेजी से काम करना होगा। आयुक्त ने कहा कि सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता किसानों को समय पर गन्ना भुगतान सुनिश्चित करना है। इसके लिए जरूरी है कि चीनी मिलें अपनी आय बढ़ाने के नए स्रोत विकसित करें, ताकि आर्थिक स्थिरता बनी रहे और किसानों के भुगतान में देरी न हो। यह बातें उन्होंने राजधानी लखनऊ में आयोजित दो दिवसीय 21-22 मई 2026 को अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन 'फ्यूचर रेडी शुगर उद्योग: सस्टेनेबल ग्रोथ की राह के उद्घाटन अवसर पर कहीं। सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश शुगर मिल्स एसोसिएशन और ग्रीनटेक कंसल्टेंट्स, कानपुर द्वारा किया गया।

सम्मेलन का मुख्य विषय 'फ्यूचर रेडी शुगर इंडस्ट्री पाथवे फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ रखा गया था। सम्मेलन में गन्ना उत्पादकता बढ़ाने, जैव-अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, जल संरक्षण, हरित ऊर्जा और भविष्य के लिए तैयार चीनी उद्योग पर व्यापक चर्चा हुई।

नवाचारों के जरिए चीनी उद्योग को मिलेगी गति

साउथ अफ्रीकन शुगर टेक्नोलॉजिस्ट एसोसिएशन (SASTA) के अध्यक्ष मुहम्मद कड़वा ने दक्षिण अफ्रीका के चीनी उद्योग के अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि कैसे वैश्विक स्तर पर डिजिटल तकनीक और ऑटोमेशन के जरिए उत्पादकता में सुधार किया जा सकता है।

डीसीएम श्रीराम लिमिटेड के ईडी एवं सीईओ आर.एल. टामक ने 'चीनी उद्योग - विजन 2047' पर अपनी प्रस्तुति दी। उन्होंने देश की आजादी के 100वें वर्ष



(2047) तक चीनी मिलों को पूरी तरह से 'बायो-रिफाइनरी के रूप में तब्दील करने का खाका पेश किया, जहां चीनी सह-उत्पाद होगी और मुख्य ध्यान ग्रीन एनर्जी, बायो-एथेनॉल तथा सस्टेनेबल एंविपेशन फ्यूल (एसएफ) पर होगा।

JPMA पुणे की जीएम-डिजाइन श्रीमती प्राची अभिजीत अपशंकर ने गन्ने की पेराई के दौरान मिलों की डिजाइनिंग और दक्षता में सुधार पर तकनीकी विचार रखे। उन्होंने समझाया कि कैसे न्यूनतम पानी के उपयोग से अधिकतम रस निकाला जा सकता है।

बायो-एनर्जी हब और AI से ही फ्यूचर रेडी बनेगा चीनी उद्योग

कॉनफ्रेंस में मवाना शुगर्स के प्रबंध निदेशक (MD) आर. के. गंगवार ने चीनी उद्योग के भविष्य की रूपरेखा पेश की। उन्होंने उद्योग को आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने के बार मुख्य स्तंभों पर जोर दिया। श्री गंगवार ने कहा कि वैश्विक ऊर्जा संकट को देखते हुए भारतीय चीनी मिलों को केवल चीनी उत्पादन तक सीमित न रहकर 'बायो-एनर्जी हब के रूप में विकसित होना होगा, जिसके लिए एथेनॉल और डिस्टिलरी क्षमताओं का विस्तार जरूरी है। उन्होंने गन्ने की खेती से लेकर मिल प्रोसेसिंग तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल मैपिंग तकनीक अपनाने की वकालत की, ताकि आने वाले 15-20 वर्षों के बदलावों के लिए मिलें आज से ही तैयार हो सकें।

ऊर्जा संकट में चीनी उद्योग का बढ़ा महत्व

प्रो. नरेंद्र मोहन ने अपने संबोधन में कहा कि बदलते वैश्विक ऊर्जा समीकरणों और खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों के बीच चीनी उद्योग रणनीतिक पुनर्मूल्यांकन बेहद जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि चीनी उद्योग अब केवल चीनी उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एथेनॉल और हरित ऊर्जा का बड़ा स्रोत बन चुका है।

शर्करा भूषण पुरस्कार' से सम्मानित हुए विशेषज्ञ

कार्यक्रम के दौरान चीनी उद्योग में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कई विशेषज्ञों को 'शर्करा भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

सम्मान पाने वालों में सी. बी. पटोदिया, प्रो. नरेंद्र मोहन, पी. एस. गहलोत, रोशन लाल टामक, शंकर लाल शर्मा और वी. एस. बंका शामिल रहे।

कई देशों के विशेषज्ञ हुए शामिल

सम्मेलन में थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका, मिस्र, ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका और फिलीपींस सहित कई देशों के विशेषज्ञों ने भाग लिया। इसके अलावा देश के चीनी उद्योग से जुड़े कई प्रमुख उद्योगपति और विशेषज्ञ भी कार्यक्रम में मौजूद रहे।

Source: Sugar Times, May, 2026

Continued on the next page ...



उत्तर प्रदेश का चीनी उत्पादन एक दशक में सबसे कम, आगामी सीजन में बढ़ सकता है गन्ना आपूर्ति का संकट

आगामी सीजन में भी चीनी मिलों के सामने गन्ना आपूर्ति का गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। कमजोर मानसून की आशंका और गन्ने की खेती से जुड़ी समस्याओं ने बढ़ाई गन्ना अर्थव्यवस्था की चुनौतियां।

देश के प्रमुख चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती और शुगरकेन इकॉनमी की चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। चालू चीनी वर्ष 2025-26 में 15 मई तक प्रदेश की चीनी मिलों में पिछले वर्ष के मुकाबले 73 लाख टन कम गन्ने की पेराई हुई और राज्य के चीनी उत्पादन में 2.75 लाख टन की गिरावट दर्ज की गई।

गन्ने से चीनी रिकवरी में बढ़ोतरी के बावजूद उत्तर प्रदेश में चीनी उत्पादन घटकर 89.70 लाख टन रह गया, जो पिछले एक दशक का सबसे निचला स्तर है। वर्ष 2019-20 में हुए रिकॉर्ड 126 लाख टन चीनी उत्पादन की तुलना में यूपी के चीनी उत्पादन में करीब 30 प्रतिशत की गिरावट आ चुकी है।

उत्तर प्रदेश में चीनी उत्पादन की स्थिति-



राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2025-26 में देश का कुल चीनी उत्पादन 274.65 लाख टन रहा, जो लगातार दूसरे साल घरेलू खपत से भी कम है। चीनी उत्पादन में इस गिरावट ने देश से चीनी निर्यात की संभावनाओं पर विराम लगा दिया है। साथ ही, भविष्य में एथेनॉल उत्पादन को लेकर भी आशंकाएं पैदा हो रही हैं।

गन्ने की फसल पर रेड रॉट जैसी बीमारियों और नई किस्मों के विकास में अपेक्षित सफलता न मिलने के कारण अकेले उत्तर प्रदेश में किसानों को अनुमानित 2500-3000 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। दूसरी ओर, गन्ने की कमी के चलते चीनी मिलें अपनी पूरी क्षमता से नहीं चल सकीं और कई मिलों को समय से पहले पेराई सत्र समाप्त करना पड़ा। यह समूचे चीनी उद्योग के सामने उत्पन्न चुनौती का संकेत है, जो आगामी चीनी सीजन (अक्टूबर-सितंबर) में गंभीर संकट का रूप ले सकती है।

इस वर्ष संभावित मजबूत अल नीनो और कमजोर मानसून की आशंकाओं ने गन्ने की खेती की चुनौतियां और बढ़ा दी हैं। हालांकि, कृषि मंत्रालय के अनुसार चालू खरीफ

सीजन में 19 मई तक देशभर में 57.31 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ने की बुवाई हो चुकी थी, जो पिछले वर्ष के 56.64 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की तुलना में एक प्रतिशत से कुछ अधिक है।

लेकिन चीनी उद्योग से जुड़े सूत्रों के अनुसार, किसानों ने उत्तर प्रदेश में इस साल गन्ने का रकबा घटा दिया है। इसके पीछे खेती की बढ़ती लागत, रोग व कीटों के प्रकोप, श्रमिकों की कमी और घटती पैदावार जैसे कारण हैं। इन परिस्थितियों के चलते किसानों का रुझान गन्ने की बजाय अन्य फसलों और एग्रो-फॉरेस्ट्री की ओर बढ़ रहा है। यदि कमजोर मानसून के कारण सूखे जैसे हालात बने रहते हैं, तो प्रदेश में गन्ना उत्पादन पिछले वर्ष से भी कम रह सकता है।

Source: RuralVoice, 24th June, 2026

उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को रिकॉर्ड भुगतान, खेती में बढ़ा भरोसा और समृद्धि

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के लिए बीते कुछ वर्षों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। राज्य सरकार के अनुसार, प्रदेश के गन्ना किसानों को अब तक 3.22 लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया जा चुका है, जो देश में किसी भी राज्य द्वारा किया गया सबसे बड़ा भुगतान माना जा रहा है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और खेती के प्रति उनका विश्वास बढ़ा है। विशेषज्ञों का मानना है कि, किसानों को समय पर भुगतान और कृषि-केंद्रित नीतियों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ने किसानों की कर्जमाफी, समयबद्ध गन्ना भुगतान और कृषि सुधारों को प्राथमिकता दी, जिससे गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला।

पेराई सत्र 2025-26 के लिए सरकार ने गन्ने के मूल्य में 30 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि भी की है। इस फैसले से लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का कहना है कि, उचित मूल्य और समय पर भुगतान किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित करते हैं। उत्तर प्रदेश आज देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य बन चुका है। बेहतर बीज, वैज्ञानिक खेती, आधुनिक तकनीकों के उपयोग और मिलों की कार्यकुशलता में सुधार के कारण उत्पादन और चीनी रिकवरी दोनों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, फसली ऋण और डिजिटल फार्मर आईडी जैसी योजनाओं को भी बढ़ावा दिया है। मार्च 2026 तक प्रदेश में 2.03 करोड़ से अधिक फार्मर आईडी जारी की जा चुकी हैं, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंच रहा है और बिचौलियों की भूमिका कम हुई है। हालांकि, कृषि क्षेत्र के सामने जलवायु परिवर्तन, अनिश्चित मौसम और नई बीमारियों जैसी चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। इसके बावजूद, गन्ना किसानों में बढ़ता आत्मविश्वास और बेहतर आर्थिक स्थिति प्रदेश की कृषि विकास यात्रा का महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है।

Source: ChiniMandi, 9th June, 2026



यूपी में गन्ने की खेती में केमिकल खाद का इस्तेमाल घटाने पर फोकस, किसानों को सब्सिडी पर मिलेंगे स्प्रेयर

उत्तर प्रदेश में गन्ना विकास विभाग और इफको की संयुक्त वर्चुअल कार्यशाला में स्मार्ट उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभाव कम करने, हर चीनी मिल क्षेत्र में ट्रायल लगाने और किसानों को अनुदान पर स्प्रेयर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती को ज्यादा टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। गन्ना विकास विभाग और इफको के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को आयोजित वर्चुअल कार्यशाला में रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से होने वाले दुष्प्रभावों को कम करने और स्मार्ट उर्वरकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता आयुक्त, गन्ना एवं चीनी ने की।

सिर्फ मंजूर खादों-कीटनाशक का हो इस्तेमाल

बैठक में सभी चीनी मिलों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि किसानों तक केवल सिफारिश की गई और मंजूर खाद और कीटनाशक ही पहुंचाए जाएं। साथ ही चेतावनी दी गई कि किसी भी परिस्थिति में अधोमानक या अस्वीकृत कृषि रसायन किसानों को उपलब्ध नहीं कराए जाएं। विभाग ने इसे किसानों के हित और कृषि गुणवत्ता से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय बताया।

नैनो उर्वरक और आधुनिक कृषि तकनीक को बढ़ावा

कार्यशाला में इफको के विशेषज्ञों ने नैनो यूरिया प्लस, नैनो डीएपी, सागरिका, जैव उर्वरक, वाटर सॉल्यूबल फर्टिलाइजर और अन्य स्मार्ट उत्पादों के वैज्ञानिक इस्तेमाल की जानकारी दी। विशेषज्ञों के अनुसार, इन उत्पादों के संतुलित इस्तेमाल से मिट्टी की सेहत सुधारने, पौध वृद्धि बढ़ाने और उर्वरक दक्षता बेहतर करने में मदद मिल सकती है। साथ ही कृषि लागत घटाने और उत्पादन क्षमता बढ़ाने की संभावना भी जताई गई।

हर चीनी मिल क्षेत्र में लगाए जाएंगे प्रदर्शन प्लॉट

आयुक्त ने निर्देश दिए कि प्रदेश के प्रत्येक चीनी मिल क्षेत्र में स्मार्ट उर्वरकों के इस्तेमाल के लिए पांच-पांच प्रदर्शन प्लॉट स्थापित किए जाएं। फसल की परिपक्वता के समय इन स्थलों पर कृषक गोष्ठियां आयोजित कर किसानों के साथ परिणाम और अनुभव साझा किए जाएंगे, ताकि नई तकनीकों को जमीन पर परखा जा सके।

किसानों को सब्सिडी पर मिलेंगे 15 हजार स्प्रेयर

स्मार्ट उर्वरकों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश की गन्ना समितियों के माध्यम से किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान पर 5,000 पावर स्प्रेयर और 10,000 बैटरी स्प्रेयर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। इसका उद्देश्य किसानों को आधुनिक

कृषि उपकरणों तक आसान पहुंच देना और छिड़काव प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना है।

वृक्षारोपण अभियान और जागरूकता कार्यक्रम पर भी जोर

कार्यशाला के दौरान पर्यावरण संरक्षण को कृषि विकास से जोड़ते हुए सभी गन्ना समितियों, परिषदों और क्षेत्रीय कार्यालयों में वृक्षारोपण अभियान चलाने का आह्वान किया गया। "एक पेड़ मां के नाम" अभियान के तहत अधिकारियों और कर्मचारियों को पौधरोपण का संकल्प भी दिलाया गया। साथ ही स्मार्ट उर्वरकों, बायोफर्टिलाइजर और बायोपेस्टिसाइड के उपयोग संबंधी जानकारी किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रचार सामग्री उपलब्ध कराने और नियमित कार्यशालाएं आयोजित करने के निर्देश दिए गए।

Source: KisanTak, 8th June, 2026

SUGARCANE PEST ALERT

Lucknow: The department of sugarcane development has issued an alert regarding the protection of the cane crop from pests.

According to additional sugarcane commissioner VK Shukla, currently, due to high temperatures, an infestation of sucking pests is being observed in both the plant crop and the ratoon crop of sugarcane in Uttar Pradesh, which is likely to have an adverse impact on the crop's growth and productivity. He said that the UP Sugarcane Research Council, Shahjahanpur, has shared detailed information with farmers regarding the identification, symptoms and effective control measures for these sucking pests.

Shukla said that the Kala Chikta (black bug) infestation is typically observed during periods of high temperature and dry weather—generally from April to June—appearing more frequently in the ratoon crop and less so in the plant crop.

The leaves of affected plants turn yellow and exhibit reddish-brown spots. The nymphs (immature stages) of this pest are found lodged between the leaf sheath and the spindle (unopened leaves) of the sugarcane stalk.

Likewise, the thrips are very small insects, measuring approximately 2-3 mm in size. Their infestation spreads rapidly during periods of high temperature and dry weather. The tips of the affected leaves curl up and become pointed. The affected leaves turn white or yellow, starting from the tip and progressing down-wards. Their population begins to decline as soon as the monsoon rains commence.

Source: TOI, 6th May, 2026



UPSMA
UP SUGAR MILLS ASSOCIATION

वार्ता The Dialogue

April to June, 2026

Quarterly Newsletter of UPSMA

VOL: IV, ISSUE: 317

DRIP IRRIGATION BOOSTS UP CANE YIELDS BY 25% AS ETHANOL CAPACITY TRIPLES UNDER YOGI GOVERNMENT

The Uttar Pradesh government's sustained push for drip irrigation in sugarcane farming over the past nine years has delivered a 25 per cent increase in cane output for farmers who have adopted the technology, while ethanol production capacity in the state's sugar sector has nearly tripled since 2017, Jagran reported.

According to the Sugarcane Development and Sugar Industry Development Department, drip irrigation systems have been installed across 73,078 hectares of sugarcane area in Uttar Pradesh over the past nine years. Farmers using the technology have seen production rise by up to 25 per cent, while water usage has been reduced by up to 50 per cent. Fertiliser consumption has also fallen by a similar margin, as nutrients are dissolved directly into the irrigation water and delivered efficiently to the plant roots through the drip system, reducing both wastage and input costs.

The department noted that drip irrigation has made it possible to cultivate sugarcane in alkaline soils and low-rainfall regions where conventional farming methods were previously unviable. The number of farmers adopting the technology has continued to grow steadily as its benefits have become more widely visible.

On the ethanol front, the department said that in 2017, only 37 sugar mills in Uttar Pradesh had ethanol plants, with a combined installed capacity of approximately 88 crore litres per year, against actual production of only 42 crore litres. As of now, 53 sugar mills have ethanol production facilities, with total installed capacity expanded to approximately 258 crore litres per year. Actual ethanol production from the sugar sector has risen to 137 crore litres, reflecting the significant scale-up achieved under the current administration's bioenergy push.

Source: Chinimandi, 28th April, 2026

BALRAMPUR CHINI AND LUCKNOW CANTONMENT BOARD LAUNCH BIOPLASTICS PLATFORM

Lucknow: Balrampur Chini Mills Limited (BCML), in partnership with the Lucknow Cantonment Board, formally launched Bioyug Green Command 2026 in Lucknow on June 5, 2026, marking World Environment Day with a platform dedicated to

advancing India's bioplastics ecosystem, the company said in a press release filed with the stock exchanges.

The event was inaugurated in the presence of Rajnath Singh, Union Defence Minister, who attended as Chief Guest. The launch marked the formal rollout of a collaboration between Balrampur Bioyug and the Lucknow Cantonment Board, following the signing of a memorandum of understanding and BCML's first institutional order for compostable Polylactic Acid (PLA)-based products earlier this year.

Speaking at the event, Vivek Saraogi, Chairman and Managing Director of Balrampur Chini Mills Limited, said the transition from conventional materials to sustainable alternatives was not only an environmental necessity but an opportunity to build new industries, strengthen domestic manufacturing, and create long-term value for society.

Avantika Saraogi, Executive Director of Balrampur Chini Mills Limited, framed the shift to biomaterials as an economic opportunity tied directly to agriculture, saying the move was about empowering farmers and creating new industries. She added that while the last century belonged to oil and petrochemicals, the next could belong to farmers and fields.

Addressing the gathering, Rajnath Singh highlighted the health hazards of microplastics, citing scientific research indicating that approximately 3,50,000 people die globally each year due to microplastic exposure, with the particles found even in the blood of newborns. He said PLA, produced from sugarcane, breaks down completely within 180 days, adding that producing bioplastic domestically would reduce India's dependence on foreign raw materials and strengthen economic resilience. He noted that India's existing 20 per cent ethanol blending in petrol had already shielded the country from supply chain disruptions during the recent West Asia crisis, and said raising the blend to 35 per cent would further solidify self-reliance. He also cited economist projections that the global bioplastics market could reach \$120 billion in value by 2075-2090.

Source: Chinimandi, 8th June, 2026

UPSMA Newsletter titled 'Varta' the Dialogue is providing information on sugar, sugar industry and sugar byproducts. We request you to share your thoughts and experience with us through write-ups, success stories, updates, photographs etc. We publish your creative in the next edition of this newsletter. You are requested to send your entries to be published in UPSMA newsletter through mail at upsma@upsma.org. The newsletter will be uploaded on UPSMA website.

अस्वीकरण: यहाँ दी गई जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा या अन्य स्रोतों से ली गई है, जिन्हें विश्वसनीय माना जाता है और इस पर इस तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। इस समाचार में दी गई जानकारी में किसी भी अनजाने त्रुटि से किसी भी व्यक्ति को होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के लिए 'वार्ता टीम' किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगी। इस दस्तावेज़ में दी गई जानकारी इस समाचार की तारीख तक है और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि भविष्य के परिणाम या घटनाएँ इस जानकारी के अनुरूप होंगी।

Glimpse of the International Conference (2nd Edition)

Organised by



held at Lucknow
on 21 & 22 May, 2026

